नजरिया

बुंदेलखंड को सबका सहयोग चाहिए

भूख, कुपोषण व पेयजल की कमी से जूझ रहे इस इलाके को संवेदनशील दृष्टिकोण की जरूरत है।

हिन्दुस्तान

भारत डोगरा
सामाजिक कार्यकर्ता

29-12-15

पिछले गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड के गंभीर रूप से सूखाग्रस्त इलाकों को राहत देने के इरादे से कई घोषणाएं कीं, जैसे मनरेगा, सस्ते अनाज व पेयजल की उपलब्धता में जरूरी सुधार लाना। ये निर्देश पहले ही आ जाते, तो ज्यादा बेहतर होता, फिर भी इन घोषणाओं का स्वागत किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के 13 जिलों में फैले बुंदेलखंड में भूख, कुपोषण, पशुओं के लिए चारे और पेयजल की कमी की स्थिति विकट हो चली है। वहां से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। हालांकि मजदूरी न मिलने या कम मिलने या फिर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अनेक प्रवासी मजदूर भी संकट में हैं। इसलिए स्थानीय स्तर पर राहत के कार्य और जरूरी हो गए हैं।

मनरेगा जैसे रोजगार कार्यक्रमों की बहुत जरूरत तो है, लेकिन पहले से बकाया मजदूरी महीनों तक न मिलने के कारण लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा कि इससे जरूरी राहत मिलेगी। ऐसे में, सरकार बकाया मजदूरी देने के साथ यह सुनिश्चित करे कि मजदूरी एक सप्ताह के अंदर-अंदर निश्चित तौर पर मिल जाएगी। चूंकि इस इलाके के लोग पहले ही शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हैं, इसलिए उनके काम करने की शर्तें भी उदार और आसान होनी चाहिए। कार्यों में थोड़ी-बहुत कमी होने पर मजदूरी काटनी नहीं चाहिए। मनरेगा के काम जल और मिट्टी संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के वैज्ञानिक, सुनियोजित प्रयासों पर आधारित होने चाहिए। लोगों की जेब में पूरी रकम पहुंचे, इसके लिए भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई बहुत जरूरी है। पशुओं के लिए चारे की बेहतर उपलब्धता भी जरूरी है। व्याकुल पशुओं के लिए जल-स्रोतों के पास बाड़े बनवाकर वहां उनके लिए चारे व पानी की व्यवस्था की जा सकती है। पेयजल की स्थिति पर पैनी नजर रखनी चाहिए, ताकि किसी भी गांव में संकट के असहनीय होने के पहले ही स्थिति संभाली जा सके।

यह अत्यंत अफसोसनाक बात है कि खरीफ की फसल की क्षति का मुआवजा अभी तक ज्यादातर किसानों को नहीं मिला है, जबकि जरूरत यह है कि किसानों के साथ-साथ बटाईदारों को भी यह मदद मिले। ऐसे संकट के वक्त विपक्षी दलों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें जन-समस्याओं की तरफ सरकार व प्रशासन का ध्यान खींचने के साथ-साथ भ्रष्टाचारियों पर भी पैनी नजर रखनी चाहिए। साथ ही, अपने स्तर पर भी लोगों को राहत पहुंचाने की रचनात्मक पहल करनी चाहिए। सामाजिक संगठन भी ऐसी जिम्मेदारियां स्वयं निभाने के साथ दूर-दूराज के गांवों की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं।

मूल बात यह है कि संकट के समय में समाज के सभी तबकों का रचनात्मक योगदान ऐसे संकट से निपटने में बना रहे। जाहिर है, समाज की संवेदनशीलता को बढ़ाने में मीडिया की अहम भूमिका है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)